भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.07.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 960 का उत्तर

के-रेल (सिल्वरलाइन) परियोजना

960. श्री हैबी ईडन:
श्री के. मुरलीधरनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल सरकार ने के-रेल (सिल्वरलाइन) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने दिनांक 07.12.2022 को या उसके बाद के रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना के अनुमोदन और अनुमति के लिए नए दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए पत्राचार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिनांक 07.12.2022 को या उसके बाद इस परियोजना की पुनः जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या परामर्शदात्री कंपनी सिस्ट्रा द्वारा तैयार की गई पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट में यह पाए जाने के बाद कि यह परियोजना व्यवहार्य नहीं है, के-रेल ने रेलवे बोर्ड को एक अवैध और अमान्य व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): रेल मंत्रालय द्वारा केरल रेल विकास निगम लिमिटेड को कभी भी इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का सुझाव नहीं दिया गया है क्योंकि यह परियोजना अभी स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, यह बताया गया है कि केरल सरकार ने केरल रेल विकास निगम लिमिटेड को

कहा है कि वह भूमि अधिग्रहण इकाइयों में पहले से तैनात अधिकारियों को केरल रेल विकास निगम लिमिटेड की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तैनात करे।

(ख) और (ग): रेलवे बोर्ड द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को केरल रेल विकास निगम लिमिटेड ने दक्षिण रेलवे को प्रस्तुत कर दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण रेलवे को जांच पूरी करने के लिए उचित कार्रवाई करने और केरल रेल विकास निगम लिमिटेड को आगे की कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय रेलवे की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ): परियोजना का व्यवहार्यता-एवं-अर्थक्षमता अध्ययन मैसर्स सिस्ट्रा द्वारा किया गया है और केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है।

****

s.k